



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1938 (श0)

(सं0 पटना 38) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जनवरी 2017

सं० 08/आरोप-01-97/2015-15865 सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 नवम्बर 2016

श्री सरयुग दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-288/08, 116/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ (मधुबनी) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6709, दिनांक 22.06.2010 द्वारा सोलर लाईट अधिष्ठापन में सरकारी राशि के दुरुपयोग एवं गबन संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्यवाई का अनुरोध किया गया।

सम्यक् विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11947, दिनांक 28.08.2012 द्वारा श्री दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी। श्री दास की सेवानिवृत्ति (दिनांक 30.09.2012) के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-15334, दिनांक 07.11.2012 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-972 दिनांक 02.07.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-13929, दिनांक 14.09.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री दास से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री दास का स्पष्टीकरण (दिनांक 02.03.2016) प्राप्त हुआ।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दास के लिखित अभिकथन की समीक्षा में यह पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ के पद पर पदस्थापन के दौरान आरोपित पदाधिकारी ने सरकार के निदेश एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रतिष्ठान से सोलर लाईट का क्रय कर अधिष्ठापन कराया, जबकि उक्त कार्य बेल्टान के माध्यम से कराया जाना था। इस क्रम में प्रति यूनिट अधिक राशि का भुगतान किये जाने से राजस्व की क्षति हुई। यद्यपि जाँच पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में योजना सं०-01/08-09 की प्राक्कलित राशि (7,31,200.00 रुपये) के विरुद्ध 6,01,200.00 रुपये का भुगतान किये जाने के आधार पर सरकारी राशि का गबन प्रमाणित नहीं बताया है, तथापि श्री दास द्वारा प्रति युनिट क्रय हेतु स्वीकृत राशि 45,700.00 के आधार पर शेष राशि के लिए आपूर्तिकर्ता के लंबित दावे संबंधी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। इसके आलोक में राजस्व क्षति का आरोप प्रमाणित होता है। बी०पी०एल० सूची तैयार करने के क्रम में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया, जिसे जाँच पदाधिकारी ने भी प्रमाणित बताया। इन्दिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के विपरीत मनमाने

ढंग से इन्दिरा आवास का आवंटन किया गया। गलत मंशा रखते हुए प्रतीक्षा सूची में छेड़-छाड़ किया गया। इन्दिरा आवास योजना के वर्षवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध काफी कम संख्या में आवास की स्वीकृति प्रदान की गयी। उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों पर श्री दास द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत श्री दास के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) कटौती 10 (दस) वर्षों तक करने का निर्णय विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-10660, दिनांक 04.08.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा पेंशन कटौती के उक्त प्रस्ताव में दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2136, दिनांक 19.10.2016 से प्राप्त हुई।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत श्री सरयुग दास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-288/08, 116/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय संसूचित किया जाता है :-

(क) पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) की कटौती 10 (दस) वर्षों तक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 38-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>